उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(09/32)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सीएम हाउस स्थित कैंप कार्यालय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य को इन्वेस्टमेंट हेतु देश के सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। राज्य को अन्य राज्यों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे निकलना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को सही मायने में इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए सभी विभागों और अन्य साझेदारों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सफलता के लिए निवेशकों की सुविधा हेतु बनाए गए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल को पूर्ण रुप से प्रभावी बनाया जाए। एक ही स्थान पर निवेशक को सभी प्रकार की सूचनाएं व आवश्यक दिशा–निर्देश और मदद प्राप्त होनी चाहिए। निवेशकों की आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित किए जाने चाहिए। जिससे उनको प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सके।

प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्रस्तावित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत राज्य में व्यवसाय करने से संबंधित विभिन्न कारकों के क्रियान्वयन की स्थिति का पता करते हुए अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर कार्ययोजना विकसित की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा, ऑनलाइन प्रक्रिया, सेवाओं की व्यापक सूची, एकल खिड़की की उपलब्धता, सरकार के स्तर पर दी जाने वाली सुविधाएं, औद्योगिक संघों के साथ नियमित बैठक जैसे कई बिंदुओं पर विचार किया जाता है। भारत सरकार के वर्ष 2016 की रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम 10 राज्यों में शामिल था। उत्तराखण्ड लीडर श्रेणी का राज्य है। डी.आई.पी.पी. द्वारा निर्धारित 340 प्वाइंट्स में से 96.13 प्रतिशत बिंदुओं पर अनुपालन किया गया है। 10 सुधार क्षेत्रों में से 7 क्षेत्रों में 100 प्रतिशत उपलब्धि रही है। उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इस वर्ष रैंकिंग में स्टेकहोल्डर से भी फीडबैक लिया जाएगा। जिसमें नये व्यवसायी, विद्यमान व्यवसायी, आर्किटेक्ट, विद्युत कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिवक्ता आदि होंगे।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 के लिए न्याय विभाग को वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय शुल्क और प्रक्रिया शुल्क का मर्जर अक्टूबर तक करना है। इसी प्रकार आवास और शहरी विकास विभाग को स्थानीय निकायों के लिए मास्टर प्लान बनाना है साथ ही मकानों के नक्शे पास करने का ऑनलाइन प्रबंध करना है। रजिस्ट्रेशन विभाग को अभिलेखों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार लाना है। राजस्व विभाग को भूलेख सॉफ्टवेयर को तीव्रता से लागू करना है। साथ ही भू–अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु कार्यवाही करनी है। राजस्व विभाग को राजस्व न्यायालयों के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाना है। ऊर्जा विभाग को विद्युत निरीक्षणालय हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण करना हैं। नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग को भार एवं माप विभाग हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है। वन विभाग को रवन्ना हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है। ड्रग कंट्रोलर को ड्रग मैनुफैक्चरिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाना है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वह 30 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2017 के मध्य अपने निर्धारित कार्य को पूर्ण कर लें।

बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय, एम.डी. सिडकुल श्री आर.राजेश कुमार सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 08 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(09/31)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में चारधाम ऑल वेदर रोड तथा टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम ऑल वेदर रोड, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसको निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिये सभी संबन्धित विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा। सभी संबन्धित जिलाधिकारी ऑल वेदर रोड से संबन्धित भू–अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, मुआवजा निर्धारण जैसे कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर करें। मुख्यमंत्री ने भू–अधिग्रहण, मुआवजा वितरण एवं वन भूमि मामलों के लिये पूर्व निर्धारित 30 सितम्बर की डेडलाइन के अन्दर काम पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आरबिट्रेशन के प्रकरणों को समय से निस्तारित किया जाय। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त कन्सलटेंट एजेंसियों को अपने पर्याप्त प्रतिनिधि नियुक्त करने के निर्देश दिये गये, जिससे किसी भी स्तर पर देरी न हो। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को इस प्रोजेक्ट की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाइवे अथारिटी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों द्वारा बुलाई जाने वाली मीटिंग में उनका कोई सक्षम प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में लगभग 52 प्रतिशत मामलों में स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्व विभाग द्वारा अभी तक 43 प्रतिशत भू–अधिग्रहण की प्रगति बताई गई, जिसमें सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

बताया गया कि ऋषिकेश–रूद्रप्रयाग(140 कि.मी.) हेतु 2089.11 करोड रूपये सिविल वर्क, 56.88 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 20 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 2165.99 करोड रूपये आगणित है। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग–माना(160 कि.मी.) हेतु 1329.37 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 162.15 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 50.56 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1542.08 करोड़ रूपये आगणित है। ऋषिकेश–धरासू(144 कि.मी.) हेतु 1320.53 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 263.58 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 43.2 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1627.31 करोड़ रूपये आगणित है। धरासू–गंगोत्री(124 कि.मी.) हेतु 1979.43 रूपये करोड़ सिविल वर्क, 73.56 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 26 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 2078.99 करोड़ रूपये आगणित है। धरासू–यमुनोत्री(95 कि.मी.) हेतु 1797.95 रूपये करोड़ सिविल वर्क, 90.79 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 31.38 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1920.12 करोड़ रूपये आगणित है। रूद्रप्रयाग–गौरीकुण्ड(76 कि.मी.) हेतु 1054.088 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 26.36 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 25.5 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1105. 948 करोड़ रूपये आगणित है। टनकपुर–पिथौरागढ(150 कि.मी.) हेतु 1408.33 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 99.82 करोड रूपये भू–अधिग्रहण, 48.72 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण कार्यों को मिलाकर कुल लागत 1556.87 करोड़ रूपये आगणित है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना में 10978.81 करोड़ रूपये सिविल वर्क, 773.14 करोड़ रूपये भू–अधिग्रहण, 245.36 करोड़ रूपये वन भूमि हस्तांतरण के कार्यों को मिलाकर 11997.31 करोड़ रूपये की लागत आगणित है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव राजस्व श्री हरबंश चुघ, जिलाधिकारी चमोली आशीष जोशी, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मंगेश घिल्डियाल, अपर सचिव श्री विनोद सुमन सहित वन विभाग, राजस्व, लोनिवि, एनएच, बीआरओ के अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 08 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(09/30)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालय दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि हिमालय एक व्यक्ति विशेष का नहीं, एक समाज का नहीं, एक राज्य विशेष का नहीं, ये पूरे देश और दुनिया का है। इसलिए आवश्यक हो जाता है की हम इस हिमालय दिवस पर देश और दुनिया का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करे और सभी लोग सामूहिक रूप से संकल्प ले की हम हिमालय को बचायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हिमालय विश्व की महानतम पर्वत श्रंखला है। हिमालय अपनी नदियों और जलवायु से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। हमारा राज्य हिमालयी क्षेत्र का नवीनतम राज्य है। गंगा, यमुना और कई जीवनदायिनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। हिमालय उत्तराखंड के लिए एक वरदान है क्यूँकि यहाँ आस्था के प्रतीक चारधाम तो स्थित है ही साथ ही इसकी मनोरम वादियां और प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन एवं आर्थिक विकास के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध करवाते है। पलायन एवं बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए हिमालय के सभी संसाधनों को सरंक्षित रखते हुए उनका पूरी तरह से सदुपयोग करना आज समय की मांग है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हिमालयी संसाधनों के संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए एक रोड मैप तैयार कर उसे आम जनजीवन और सरकार की नीतियों से जुड़ना समय की मांग है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 7055007009

देहरादून 08 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(09/29)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में बर्मिंघम इंडस्ट्रियल एक्सपो से लौटे 08 शिल्पियों के दल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शिल्पियों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपने अनुभव से उत्तराखण्ड में और अधिक लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव उद्योग को निर्देशित किया कि जो भी शिल्पी विदेश का अनुभव लेकर लौटे हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए एक मीटिंग की जाए और फिर सरकारी स्तर से जो भी मदद हो उनको दी जाए। मुख्यमंत्री ने शिल्पियों से कहा कि आधुनिक समय में गुणवत्ता के साथ–साथ डिजाइन और फैशन का भी बहुत महत्व है। उत्तराखण्ड के उत्पादों को फैशन में लाना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय शिल्प और कला को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। सरकार न सिर्फ इसके लिए प्रशिक्षण दे रही है बल्कि विपणन केंद्रों के विकास के लिए भी संकल्पित है।

प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि 04 सितंबर को बर्मिंघम में आयोजित इंडस्ट्रियल एक्सपो में गए भारतीय दल में उत्तराखंड के 08 शिल्पी सम्मिलित थे। उत्तराखंड के शिल्पियों ने नेचुरल फाइबर, ऊन और कॉपर के सामानों का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि एक्सपो में बहुत से व्यापारियों ने उत्तराखण्ड के उत्पादों में रुचि दिखाई। विशेष रुप से नेचुरल फाइबर और ऊन के स्टोल्स और शॉल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कॉपर से निर्मित उत्पादों की प्रशंसा हुई। इस दौरे से उत्तराखण्ड के शिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव प्राप्त हुआ और इसके साथ ही उन्हें बाजार की मांग की जानकारी भी मिली। उन्होंने बताया कि यह सभी शिल्पी मास्टर क्राफ्ट मैन है और प्रत्येक शिल्पी 100–100 शिल्पियों को प्रशिक्षित करेगा। बर्मिंघम के दल में उत्तरकाशी के श्री चंद्र लाल, श्री नरेश, अल्मोड़ा के श्री बलवंत टम्टा, बागेश्वर के श्री शिव लाल, चमोली के श्री धरमलाल और श्रीमती गुड्डी देवी तथा हरिद्वार के श्री मुकेश और आशु सम्मिलित थे।

अपर निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड के शिल्पियों के दल ने बर्मिंघम , यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उद्योग मेले में 04 सितंबर को प्रतिभाग किया था। यह दल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट और उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में बर्मिंघम में स्थापित भारतीय पवेलियन में सम्मिलित हुआ था।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग / 7055007009